

जगन्नाथ प्रसाद

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

3 मई, 1962

(जे. एल. कपूर, के. सी. दास गुप्ता और रघुबर दयाल, जे. जे.,)

यदि बिक्री कर अधिकारी की शिकायत आवश्यक है तो अभियोजन - बिक्री कर अधिकारी, क्या न्यायालय - कर का भुगतान करने का दायित्व - कराधान के लिए एकल बिंदु निर्धारित करने वाली अधिसूचना अप्रभावी - उत्तर प्रदेश सैलू कर अधिनियम, 1948 (1948 का यू.पी. 15) धारा 3, 3 ए, का प्रभाव 14(डी) आपराधिक अपराध संहिता 1898 (1898 का अधिनियम 5), धारा 195।

- अपीलार्थी जो वनस्पति घी में व्यवसाय करते हैं ने यू. पी. के बाहर चार फर्जी फर्मों के नाम से वनस्पति घी खरीदा। बिक्री कर के अपने रिटर्न में उन्होंने इन लेनदेन की बिक्री आय को इस आधार पर शामिल नहीं किया कि उन्होंने चार फर्मों से खरीदारी की थी और यह कि यूपी की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना के तहत किया गया था। बिक्री कर अधिनियम, बाहरी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चार फर्मों को की गई बिक्री पर केवल एक बिंदु पर कर लगाया जाता था। इसके समर्थन में अपीलकर्ता नंबर 1 ने बिक्री फैंक्स अधिकारी के समक्ष गलत बयान दिया और उसके समक्ष जाली बिल भी दाखिल किए। रिटर्न को सेल्स टैक्स अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन लेनदेन द्वारा कवर की गई बिक्री पर कर नहीं लगाया गया था। अपीलकर्ताओं पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए 471 भारतीय दंड संहिता के तहत और धोखाधड़ी से भुगतान से बचने के लिए अधिनियम की धारा 14 (डी) के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। अधिनियम

के तहत देय कर का अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 471 के तहत अपराध के लिए मुकदमा अवैध था क्योंकि बिक्री आयकर अधिकारी द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी जैसा कि अपेक्षित था। धारा 195 आपराधिक प्रक्रिया संहिता और अधिनियम की धारा 14 (डी) के तहत अपराध नहीं बनाया गया क्योंकि धारा 3ए के तहत कोई कर देय नहीं था, जिसके तहत जारी अधिसूचना अमान्य थी।

अभिनिर्धारित किया गया कि बिक्री कर अधिकारी न्यायालय में नहीं था। धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए शिकायत करना उनके लिए आवश्यक नहीं था। धारा 471 भारतीय दंड संहिता के तहत एक बिक्री कर अधिकारी केवल कर के मूल्यांकन और संग्रहण के उद्देश्य से राज्य का एक साधन था और भले ही उसे कुछ अर्ध-न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती थी, फिर भी वह न्यायपालिका का हिस्सा नहीं था। बिक्री कर अधिकारी के कार्यों की प्रकृति और उनके उनके निष्पादन के लिए निर्धारित तरीके से पता चलता है कि उसकी तुलना किसी न्यायालय से नहीं की जा सकती। न ही उसे राजस्व न्यायालय कहा जा सकता है। यद्यपि संहिता की धारा 195 में न्यायालय की परिभाषा को 1923 के संशोधन द्वारा "साधन" शब्द के स्थान पर "शामिल" शब्द के प्रतिस्थापन द्वारा विस्तारित किया गया था, लेकिन इसने "राजस्व न्यायालय" की परिभाषा को नहीं बदला।

श्रीमती. उज्जम बाई बनाम, उत्तर प्रदेश राज्य, (1963) 1 एस सी. आर. 778)

ऑस्ट्रेलिया की शेल कंपनी लि. बनाम फेडरल कराधान आयुक्त [1931] ए. सी. 275 और ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण [1954] 2 एस. सी. आर. 955 ने आवेदन किया।

कृष्ण बनाम गोसेरधानैया, ए. आई. आर. 1954 मैड. 822, स्वीकृत किया गया।

पुनः उत्तर -पूनमचंद मानेकलाल, (1914) आई. एल., आर. 38 बोम. 642 और

राज्य बनाम नेमचंद पशवीर पटेल, (1956) 7 एस। टी. सी.404 स्वीकृत नहीं है।

पुनः उत्तर : आर. नटराज अय्यर (1914) आई. एल. आर. 36 मैड। 72 और श्री विरेन्द्र कुमार सत्यवादी बनाम पंजाब राज्य, [1955] 2 एस. सी. आर. 1013 संदर्भित है।

माना गया, इसके अलावा अपील में लोगों को सही तरीके से दोषी ठहराया गया एस के तहत अधिनियम की धारा 14 (डी)। बिक्री कर धारा 3 के तहत देय था सभी बिक्री के संबंध में अधिनियम के। लेकिन धारा 3 ए के तहत यह था यदि सरकार ने जारी किया है तो केवल एक ही बिंदु पर लगाया जा सकता है अधिसूचना किस बिंदु पर कर की घोषणा करती है। देय था और यह नियमों द्वारा निर्धारित किया गया था। अधिसूचना के तहत द्वारा जारी किये गये कर का भुगतान सरकार द्वारा ही किया जाता था वह डीलर जो माल आयात करता था और उसे बेचता था। अपीलकर्ता घी का आयात करने पर कर का भुगतान करना पड़ता था इस घी की बिक्री से 'उन्होंने धोखाधड़ी की।' हालाँकि कोई नियम नहीं बनाये जाने के कारण अधिसूचना अप्रभावी थी अधिनियम के तहत एक बिंदु निर्धारित करते हुए, इससे अपीलकर्ताओं को कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि इसका एकमात्र प्रभाव यह था कि एस. 3 ए चलन में नहीं आया। के तहत अप्रभावी अधिसूचना का लाभ प्राप्त करने हेतु। 3-ए अपीलकर्ताओं ने भुगतान से परहेज किया के अंतर्गत कर. 3 जिसे वे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : अपराधी अपील सं., 152/59।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, के आपराधिक अपील पुनरीक्षण सं. 1182/1957 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12 मई, 1959 से विशेष अनुमति द्वारा

नूर-उद-दीन अहमद, जे. बी. दादाचंजी, ओ. सी. माथुर और रविंदर नारायण अपीलार्थियों की ओर से।

जी. सी. माथुर और सीए लाल प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश कपूर,जे. द्वारा 3 मई,1962 को पारित किया गया :

अपीलकर्ता पिता और पुत्र हैं जो अलीगढ़ में वनस्पति घी का व्यवसाय करते हैं। 'अपीलकर्ता जगन्नाथ-प्रसाद के दूसरे बेटे रोमेश के साथ उन पर धारा 14 (घ) यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 (यू. पी. 15) के तहत मुकदमा चलाया गया। 1948 का) इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है और धारा के तहत 471 धारा के साथ पढ़ें। 468 और भारतीय दंड संहिता की धारा 417 के तहत उन सभी को 'आरोप से बरी कर दिया गया था धारा 468. के तहत जगन्नाथ-प्रसाद धारा. 471 दोषी ठहराया गया था। और भारतीय दंड संहिता की धारा 417 और अधिनियम की धारा 14 (घ) के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। धारा 471, के तहत एक के लिए 'कठोर कारावास' और '1,000/- रुपये का जुर्माना। धारा 417 के तहत और एक खोज के लिए रु.1,000 से अधिनियम। भगवान दास को धारा 14 (घ) के तहत दोषी ठहराया गया था। 14 (घ) अधिनियम के 'और 1,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। रोमेश को बरी कर दिया गया। जगन्नाथ प्रसाद को दी सजाएं समवर्ती थीं। सत्र न्यायाधीश के समक्ष उनकी अपील खारिज कर दी गई और पुनरीक्षण में कहा गया: उच्च न्यायालय 'जगन्नाथ प्रसाद' को धारा 417 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध से बरी कर दिया गया था। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय और आदेश पर अपीलकर्ता इस पर आए हैं।

अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य ये हैं: ~ 1950-51 में, अपीलकर्ताओं की फर्म ने लगभग रु. मूल्य की सब्जी-घी खरीदी। चार फर्जी फर्मों के नाम पर यूपी राज्य के बाहर के स्थानों से 3 लाख रुपये। फर्म ने उस वर्ष के लिए बिक्री कर अधिकारी

अलीगढ़ को अपना रिटर्न दिया और इसमें इन लेनदेन की बिक्री आय शामिल नहीं की इस आधार पर कि उन्होंने इन्हें इन चार फर्मों से खरीदा था, जिन्हें हाथरस, अलीगढ़ और यूपी के अन्य स्थानों में कारोबार करना था ~ इस प्रकार इन लेनदेन की बिक्री की आय को शामिल न करके फर्म ने बिक्री कर के भुगतान से चोरी की। उस वर्ष पर• थोर लेनदेन। फर्म द्वारा किए गए बिक्री कर के रिटर्न को बिक्री कर अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप माल की बिक्री को कवर किया गया था। लेन-देन पर कर नहीं लगता था। इन लेनदेन के संबंध में कर अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई थी; एक जांच आयोजित की गई जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं और एलटोमेश को ऊपर बताए गए अनुसार दंडित किया गया और गैर-दोषी ठहराया गया। हाईकोर्ट में तथ्यों को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। इ। निचली अदालतों का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ताओं की कंपनी ने बाहर से वनस्पति घी खरीदा। पी. और उन सामानों की बिक्री की आय को इस आधार पर नहीं दिखाया कि वे सीजे राज्य के अंदर से खरीदे गए थे। पी. जबकि वास्तव में वे राज्य के बाहर से खरीदे गए थे, अपीलकर्ता जगन्नाथ प्रसाद द्वारा 'सेल्स टैक्स ऑफिसर' के समक्ष दिए गए बयान झूठे थे और 'सेल्स' टैक्स ऑफिसर के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल जाली थे। दोषसिद्धि को चुनौती दी गई।

हमसे पहले पाँच अंक उठाए गए थे:(1) 1950-51 में अधिनियम की धारा 3 ए के तहत इन लेनदेन पर बिक्री कर देय था और देनदारी उत्पन्न हुई 1952 में अधिनियम में संशोधन। जिसने अनुभाग को पूर्वव्यापी संचालन दिया और बिक्री विवाद पर लागू हो गया और इसलिए वहां पूर्व तथ्यात्मक संशोधन के तहत कोई अभियोजन नहीं चलाया जा सकता; (2) धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बिक्री कर अधिकारी द्वारा शिकायत की कमी के कारण अपीलकर्ताओं का मुकदमा अवैध था।; (3) अधिनियम के धारा 14 (घ) के तहत कोई अपराध नहीं था।; (4) जाली चालान

अपीलकर्ता जगन्नाथ प्रसाद द्वारा पेश किए गए थे क्योंकि उन्हें बिक्री कर अधिकारी द्वारा बुलाया गया था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका उपयोग अपीलकर्ता द्वारा किया गया था और (5) बिक्री कर अधिकारी ने चालान को वास्तविक स्वीकार करने के बाद उन चालानों के संबंध में कोई अभियोजन नहीं चलाया जा सकता था।

अब अपीलार्थियों पर उनके द्वारा किए गए कथित अपराध की तारीख के बाद किसी भी संशोधन के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए हैं और इसलिए हमें अधिनियम को उस तारीख को देखना होगा जब अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था। आरोप के अनुसार अपराध 16 जुलाई, 1951 को या उसके आसपास किया गया था, जब अपीलकर्ताओं द्वारा बिक्री कर अधिकारी के समक्ष जाली-चालान पेश किए गए थे। इसलिए हमें जो देखना है वह कानून के अधिनियम की धारा 3 अधिनियम और धाराओं के तहत कर के दायित्व से संबंधित है। 3 एकल बिंदु कराधान के साथ ए, धारा के तहत 8 प्रत्येक विक्रेता को प्रत्येक निर्धारण वर्ष के अपने कारोबार पर तीन पाई प्रति रुपये की दर से कर का भुगतान करना पड़ता था। इस प्रकार कर सभी बिक्री के संबंध में देय था, लेकिन धारा 3(1) के तहत कर का भुगतान केवल एक ही बिंदु पर किया जाता था।

उस धारा ने धारा प्रदान किया। 3 ए (1) "धारा 3 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकती है कि किसी भी माल या माल के वर्ग के संबंध में कारोबार श्रृंखला में ऐसी एकल पूजा के अलावा कर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। क्रमिक विक्रेताओं द्वारा बिक्री, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

सरकार कर को एक ही बिंदु पर देय घोषित कर सकती थी लेकिन दो

आवश्यकताएँ थीं; सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना होनी चाहिए थी जिसमें उस बिंदु की घोषणा की जानी चाहिए जिस पर कर देय था और क्रमिक विक्रेताओं द्वारा बिक्री की श्रृंखला में यह 'जैसा निर्धारित किया जा सकता है' अर्थात् जैसा नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। धारा 3 ए को 1952 में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया गया था, लेकिन वर्तमान कार्यवाहियों पर पूर्वव्यापी प्रावधान लागू नहीं होता है। एस के तहत 38 जून, 1948 को एक अधिसूचना क्रमांक ख्या 1 (3) जारी की गई थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि बाहर से आयातित वनस्पति घी की बिक्री की आय को आयातक के अलावा अन्य विक्रेता के कारोबार में शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अधिसूचना का प्रभाव यह था कि यदि कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश के बाहर से वनस्पति का घी आयात करता है और उसे बेचता है तो उसे बिक्री से प्राप्त आय को अपने कारोबार में शामिल करना आवश्यक था, लेकिन अन्य विक्रेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आयातक से वनस्पति का घी खरीदा और उसे बेचा, उनकी आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के बाहर से वनस्पति का घी आयात करने वाले अपीलकर्ताओं को अधिसूचना द्वारा अपने कारोबार में आय को शामिल करने की आवश्यकता थी और इससे बचने के लिए उन्होंने झूठे चालान पेश किए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर उन काल्पनिक विक्रेताओं से वनस्पति का घी खरीदा था और इस प्रकार यदि 'अधिसूचना एक प्रभावी अधिसूचना थी तो अपीलकर्ता बिक्री कर के भुगतान से सफलतापूर्वक बच गए, जो कानून के तहत उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता थी। लेकिन यह सहमति हुई कि अधिसूचना 'जैसा निर्धारित किया जा सकता है' शब्दों को देखते हुए अप्रभावी थी क्योंकि यह मेंवल नियमों द्वारा किया जा सकता था और धारा 3 ए में तहत कोई नियम नहीं बनाए गए थे। जिसने प्रत्येक विक्रेता को बिक्री कर के लिए उत्तरदायी बना दिया यदि वह बाहरी यू. पी. से आयातक था। इस हद तक अपीलार्थियों का तर्क अच्छी तरह से स्थापित है और इसलिए धारा 3 के अनुसार केवल

अधिसूचना द्वारा सरकार: अधिसूचना एकल बिंदु कराधान निर्धारित नहीं किया जा सका, लेकिन इससे अपीलार्थियों को बहुत मदद नहीं मिलती है। धारा 3 के तहत प्रत्येक विक्रेता प्रत्येक लेन-देन पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। 3 ए ने केवल हर बिंदु पर बिक्री के संबंध में राहत दी और इस प्रकार बहु-बिंदु कराधान को रोका। यदि धारा 3 ए के तहत अधिसूचना अप्रभावी था, जैसा कि वास्तव में था, अपीलकर्ताओं को अपनी सभी बिक्री पर कर का भुगतान आदेश की आवश्यकता थी और बहु बिंदु कराधान से बचने के लिए उन्होंने एक अप्रभावी अधिसूचना का लाभ उठाया और काल्पनिक व्यक्तियों द्वारा माल का आयात किए जाने और उन काल्पनिक विक्रेताओं से उन वस्तुओं को खरीदने के झूठे अनुरोध का परीक्षण किया और इस तरह अपीलकर्ता धारा 3 के तहत बिक्री कर के भुगतान से बच जाते हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने इसका का लाभ उठाने की कोशिश की। झूठे दस्तावेजों को प्रस्तुत करके और इस तरह धारा 3 ए के तहत कर के भुगतान से बच गया। जिसे प्रत्येक विक्रेता को अपने कारोबार पर भुगतान करना पड़ता था। धारा 3 ए के तहत जारी अप्रभावी अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने की कोशिश में अपीलार्थी धारा 3 ए के तहत कर के भुगतान से बच गए। जिसे वे किसी भी मामले में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि 3 ए 14 ((घ) के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था। अधिनियम जो निम्नलिखित उपबंध करता है:—

धारा 14. "अपराध और दंड।— कोई भी व्यक्ति जो -

(ए)

(बी)

(सी)

(घ) इस अधिनियम के तहत देय किसी भी कर के भुगतान से धोखाधड़ी से बचता है,

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इस दायित्व में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने में, वह एक हजार रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, और जहां भंग एक निरंतर भंग है, तो पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जारी है"।

यह कहना कोई बचाव नहीं है कि अपीलकर्ताओं को बिक्री कर अधिकारी ने चालान पेश करने के लिए कहा था। अपीलकर्ता लगभग 3 लाख मूल्य के माल की बिक्री को अपने टर्नओवर से बाहर करने की कोशिश कर रहे थे और इस संबंध में बिक्री कर अधिकारी के समक्ष बयान दिए थे। 9 जुलाई, 1951, और यह साबित करने के लिए कि माल को टर्नओवर में शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी चालान अपीलकर्ता रामनाथ द्वारा प्रस्तुत किए गए थे प्रसाद. जब किसी तथ्य को किसी के समक्ष सिद्ध करना हो न्यायालय या अधिकरण और न्यायालय या अधिकरण उस व्यक्ति को बुलाता है जो किसी तथ्य पर भरोसा करता है सर्वोत्तम साक्ष्यों द्वारा इसे सिद्ध करना संभव नहीं है यदि सर्वोत्तम हो तो अपराध के अपराध के संबंध में बचाव सबूत जो, इस मामले में, इन:वाँइस बारी थे जाली दस्तावेज़ निकले। एक व्यक्ति जो . उन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करते हुए यह कहना नहीं सुना जा सकता कि उसे अपना मामला साबित करना आवश्यक था सर्वोत्तम साक्ष्य और चूँकि* होना इसलिए आवश्यक था जाली दस्तावेज़ तैयार किये

तब यह निवेदन गया कि बिक्री कर अधिकारी धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता के भीतर एक अदालत थी। और ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत की अनुपस्थिति में धारा 471 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। यह, हमारी राय में एक समान रूप से गलत प्रस्तुति है। बिक्री कर अधिकारी राज्य द्वारा कुछ करों के संग्रह के साधन हैं। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कुछ अधिकारियों को बिक्री कर अधिकारियों के रूप में

नियुक्त किया जाता है, जिन्हें करों के अधिरोपण और संग्रह के लिए कुछ कर्तव्य सौंपे जाते हैं और इस प्रक्रिया में उन्हें कई कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है जो न्यायिक प्रकृति के होते हैं और कुछ अन्य कर्तव्य जो प्रशासनिक कर्तव्य होते हैं।केवल इसलिए कि कराधान के उद्देश्य से नियोजित राज्य के कुछ उपकरणों में कुछ अर्ध-न्यायिक कार्यों को करने के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में वे अदालतों में परिवर्तित नहीं होते हैं।श्रीमती उजम बाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1953) । एससीआर, 778.) मामले में इस अदालत के हाल के एक फैसले में सभी राय इस बात पर सर्वसम्मत थी कि कर लगाने वाले अधिकारी अदालत नहीं हैं, भले ही वे अर्ध-न्यायिक कार्य करते हों।लॉर्ड सेंकी एल. सी. मे ऑस्ट्रेलिया की शेल कंपनी लिमिटेड बनाम फेडरल कमिशनर ऑफ टैक्सेशन में का निम्नलिखित अवलोकन। ((1931)एसीआर.283) को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था:—

“अधिकारी स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि न्यायालय के कई जालों के साथ न्यायाधिकरण हैं, जो फिर भी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के दृढ़ अर्थ में न्यायालय नहीं हैं।

लॉर्ड सेंकी ने कुछ नकारात्मक प्रस्तावों को भी गिनाया कि कब एक न्यायाधिकरण 4 अदालत नहीं है।पी.297 हाय लॉर्डशिप ने कहा:—

“इस संबंध में इस विषय पर कुछ नकारात्मक प्रस्तावों को गिनना उपयोगी हो सकता है:1.एक न्यायाधिकरण आवश्यक रूप से इस सख्त अर्थ में एक अदालत नहीं है क्योंकि यह एक अंतिम निर्णय देता है, 2. न ही इसलिए कि यह गवाहों की शपथ सुनता है। 3. न ही इसलिए कि दो या दो से अधिक प्रतिद्वंद्वी पक्ष इसके सामने उपस्थित होते हैं जिनके बीच उसे निर्णय लेना होता है। 4. न ही

इसलिए कि यह ऐसे निर्णय देता है जो विषयों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। 5. न ही इसलिए कि किसी अदालत में अपील की जाती है। 6. न ही इसलिए कि यह एक निकाय है जिसमें एक पदार्थ को दूसरे निकाय द्वारा संदर्भित किया जाता है। रेक्स बनाम विद्युत आयुक्त (1924) 1 के. बी. 171 "देखें।

हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति ने श्रीमत् उज्जम भट (*) मामले में बिक्री कर अधिकारियों का वर्णन इस प्रकार किया:—

“कर अधिकारी राज्य के साधन हैं। वे न तो विधानमंडल का हिस्सा हैं और न ही वे न्यायपालिका का हिस्सा हैं। उनके कार्य करों का आकलन और संग्रह हैं और करों का आकलन करने की प्रक्रिया में वे कार्रवाई के एक पैटर्न का पालन करते हैं जिसे न्यायिक माना जाता है; इस प्रकार उन्हें व्यवहार न्यायिक न्यायालयों में परिवर्तित नहीं किया जाता है। वे अभी भी राज्य के साधन बने हुए हैं और अनुच्छेद 12 में "राज्य" की परिभाषा के भीतर हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिक्री कर अधिकारियों के पास कुछ शक्तियां हैं जो अदालतों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के समान हैं, लेकिन फिर भी वे अदालतें नहीं हैं जैसा कि समझा जाता है। 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उप-धारा में। 195 यह प्रदान किया जाता है:—

धारा 195 (2) "उप-धारा (1) के खंड (बी) और (सी) में" अदालत "शब्द में एक सिविल, राजस्व या आपराधिक अदालत शामिल है, लेकिन इसमें भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1877 के तहत एक पंजीयक या उप-पंजीयक शामिल नहीं है।

यह नहीं कहा जा सकता है कि एक बिक्री कर अधिकारी एक राजस्व अदालत है। धारा 2 (क) के तहत अधिनियम और निर्धारण प्राधिकारी को अधिनियम के तहत

मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और आर. 2 (बी) के तहत एक बिक्री कर अधिकारी का अर्थ है:- ;

“बिक्री कर अधिकारी का अर्थ है "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्कल का एक बिक्री कर अधिकारी जो कर्तव्यों का पालन करता है और ऐसे सर्कल में एक मूल्यांकन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करता है।”

इस प्रकार अधिनियम के तहत एक बिक्री कर अधिकारी केवल एक मूल्यांकन प्राधिकरण है। अधिनियम के धारा 7 के तहत, यदि बिक्री कर अधिकारी, के बाद ऐसी पूछताछ करना जो वह आवश्यक समझता है, संतुष्ट है कि किया गया विवरणी सही और पूर्ण है, वह उसके आधार पर कर का आकलन करेगा और यदि कोई विवरणी निवेदन नहीं की जाती है तो वह ऐसी पूछताछ कर सकता है जो वह आवश्यक समझता है और फिर एक व्यापारी का कारोबार निर्धारित कर सकता है। इस प्रकार उसका निर्धारण उस पूछताछ पर निर्भर करता है जो वह कर सकता है और जिसे वह आवश्यक समझ सकता है। अधिनियम की धारा 9,10 और 11 उच्च न्यायालय में अपील, संशोधन और मामले के बयान से संबंधित है। धारा 13 के तहत बिक्री कर अधिकारी को व्यवसाय और खातों से संबंधित सभी खातों, दस्तावेजों और अन्य जानकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता के लिए शक्ति दी गई है और रजिस्टर हर उचित समय पर बिक्री कर अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुले होंगे। किसी भी कार्यालय, दुकान, गोदाम, वाहन या किसी अन्य स्थान में प्रवेश करने की शक्ति है जिसमें व्यवसाय किया जाता है जो बिक्री कर अधिकारी के लिए एक अदालत होने के नाते एक विनाशकारी शक्ति है जो एक ऐसा स्थान है जहां पक्षकारों के बीच न्यायाधीश प्रशासित किया जाता है चाहे पक्षकार निजी व्यक्ति हों या राज्य में पक्षकारों में से एक

हो। धारा 23 के तहत बिक्री कर अधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए दस्तावेजों और उसके द्वारा प्राप्त जानकारी के साथ कुछ गोपनीयता संलग्न की जाती है। इसी तरह आर.43 के तहत बिक्री कर अधिकारी को कारोबार की गणना करने के लिए कुछ शक्ति दी गई है जब माल को पैसे के अलावा अन्य विचार के लिए बेचा जाता है और यह ऐसी जांच के बाद है जो वह आवश्यक समझता है। इन सभी प्रावधानों से पता चलता है कि बिक्री कर अधिकारी को अदालत के बराबर नहीं माना जा सकता है। इसलिए हमारी राय में बिक्री कर अधिकारी कोई अदालत नहीं है। कृष्ण बनाम गोवर्धन स्याह में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आयकर अधिकारी के अर्थ में न्यायालय नहीं है। धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता और इस दृष्टिकोण को इस अदालत ने श्रीमती उज्जम बट (2) मामले में स्वीकार किया था। ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण में, सार्वजनिक पूछताछ अधिनियम 1950 के तहत नियुक्त एक आयुक्त को अदालत नहीं माना गया था। उस मामले में ऑस्ट्रेलिया की शेल कंपनी बनाम संघीय कराधान आयुक्त (1) को संदर्भित किया गया था। पी.967 हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, हैल्शम संस्करण, खंड से निम्नलिखित अंश 8, पी. 526 को मंजूरी दी गई:—

“कई निकाय अदालतें नहीं हैं, हालांकि उन्हें प्रश्नों का निर्णय करना पड़ता है, और ऐसा करने में न्यायिक रूप से कार्य करना पड़ता है, इस अर्थ में कि कार्यवाही निष्पक्षता के साथ संचालित की जानी चाहिए और निष्पक्षता, जैसे कि मूल्यांकन समितियाँ, संरक्षक समितियाँ, बीमा निधियों पर किए गए दावों पर निर्णय लेने के लिए बेरोजगारी बीमा अधिनियमों के तहत गठित रेफरी का अदालत, अपने सदस्यों में से एक के आचरण पर विचार करते समय अदालतों के, एक चिकित्सा परिषद सामान्य व्यक्ति की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर विचार करते समय।”

यह परिच्छेद अब तीसरे संस्करण के खंड 9 में पी.343.

लेकिन यह निवेदन गया था कि साईं कर अधिकारी एक आकलन प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए धारा 195 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्थ के भीतर एक अदालत है। कारण यह है कि 1923 के संशोधन द्वारा "अर्थ" शब्द के स्थान में "सम्मिलित" शब्द को प्रतिस्थापित करके "न्यायालय" शब्द की भाषा का विस्तार किया गया था और अब यह धारा वही पढ़ती है जैसा कि ऊमें निर्धारित किया गया है। निस्संदेह इस परिवर्तन से विधायिका का मतलब "न्यायालय" शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाना था, लेकिन यह "राजस्व न्यायालय" शब्दों की परिभाषा को बड़ा नहीं करता है। जिस निर्णय पर हमारा ध्यान केंद्रित किया गया, वह मुख्य रूप से बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले में रे पुनेमचंद मानेकलाल पर आधारित है। उस मामले में एक आयकर कलेक्टर को शब्द के अर्थ के भीतर एक राजस्व अदालत के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था। इस आधार पर कार्रवाई की गई कि आयकर अधिनियम के अध्याय IV के तहत न्यायिक प्रक्रिया के रूपों के अनुसार की गई पूछताछ राजस्व अदालत में कार्यवाही थी। यह इस आधार पर था कि कानून के तहत राजस्व प्रश्नों को आम तौर पर व्यवहार अदालतों के संज्ञान से हटा दिया जाता था और किसी व्यक्ति और सरकार के बीच राजस्व से संबंधित विवादित प्रश्न का निर्णय करने के कर्तव्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को 'राजस्व न्यायालय' के कार्यों के साथ निवेश किया जाता था। इस दृष्टिकोण का पालन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राज्य बनाम नेमचंद पशवीर पटेल ((1936)7 एससीआर. 404.) मामले में किया। बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम के तहत बिक्री कर अधिकारियों को दी गई विभिन्न शक्तियों का उल्लेख करने के बाद अदालत ने आगे कहा कि बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम के तहत बिक्री कर अधिकारी राजस्व अदालतें थीं क्योंकि उनके पास राजस्व से संबंधित प्रश्नों को तय करने का क्षेत्राधिकार था, विशेष रूप से उन शक्तियों के साथ सशक्त हैं जो आम तौर पर

अदालत या न्यायाधिकरण की विशेषताएँ हैं जो कानून के विवादित प्रश्न या नागरिकों के अधिकारों से संबंधित तथ्य पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने आर. नटराज अय्यर में अभिनिर्धारित किया कि आयकर अधिनियम के तहत अपीलों की सुनवाई करने वाला एक संभागीय अधिकारी धारा के अर्थ के भीतर एक अदालत है। धारा 476 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लेकिन एक तहसीलदार जो मूल निर्धारण प्राधिकारी था, इसलिए नहीं था कि उसके पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था, न्यायमूर्ति सुंदरा अय्यर के निर्णय में एक अंश है, जिसका महत्व है। कहा गया था:—

“मैं देख सकता हूँ कि मैं डॉ. स्वामीनाथन से सहमत होने के लिए तैयार हूँ कि साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक अधिकार इसे रिकॉर्ड करने वाले अधिकारी को अदालत नहीं बना देगा।”

पृष्ठ 84 पर, यह कहा गया था कि पहली बार में मूल्यांकन का निर्धारण अदालत का नहीं हो सकता है, हालांकि मूल्यांकन अधिकारी के पास बयान दर्ज करने की शक्ति हो सकती है। लेकिन मूल्यांकन के खिलाफ एक अपील को कलेक्टर द्वारा उसी तरीके में निपटाया जाता है जिस तरह में एक व्यवहार अदालत द्वारा एक अपील का निपटारा किया जाता है। इस संबंध में श्री विरिंदर कुमार सत्यवाद बनाम पंजाब राज्य (1955) 2 एससीआर. 1015, 1018.) में न्यायमूर्ति वेंकरामा अय्यर न्यायमूर्ति निर्णय में निहित कानून न्यायमूर्ति कथन का संदर्भ दिया जा सकता है। वहाँ एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण और एक अदालत के बीच अंतर निम्नानुसार दिया गया था -

“यह व्यापक रूप से कहा जा सकता है कि एक अदालत को अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण से अलग करने वाली बात यह है कि उस पर न्यायिक तरीके से विवादों का फैसला करने और एक निश्चित निर्णय में पक्षों के अधिकारों की घोषणा करने का कर्तव्य है। न्यायिक

तरीके से निर्णय लेने में यह शामिल है कि पक्षकारों को अपने दावे के समर्थन में सुनवाई के अधिकार के रूप में और इसके प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है। और यह प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में विचार करने और कानून के अनुसार मामले का फैसला करने का दायित्व भी रखता है। इसलिए जब यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया कोई प्राधिकरण अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण से अलग है, आइए यह निराकृत जाना चाहिए कि क्या अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसमें अदालत के सभी गुण हैं।"

अर्ध-न्यायिक न्यायालय में निपटने के लिए यह गुल्लापेल्ट नेगेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1959) सप्प 1 एससीआर 319, 353-4.

“अर्ध-न्यायिक अधिनियम की अवधारणा का तात्पर्य है कि यह अधिनियम पूरी तरह से न्यायिक नहीं है, यह केवल कार्यकारी निकाय या प्राधिकरण पर अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कुछ कार्य करने में न्यायिक प्रक्रिया के मानदंडों के अनुरूप होने के कर्तव्य का वर्णन करता है।

अन्य मामलों को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उनका निराकृत उनके अपने तथ्यों पर और विभिन्न न्यायालय से संबंधित था। हमारी राय में एक बिक्री कर अधिकारी धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्थ में एक अदालत नहीं है। और इसलिए बिक्री कर अधिकारी के लिए शिकायत करना आवश्यक नहीं था और ऐसी शिकायत के बिना कार्यवाही क्षेत्रधिकार से बाहर नहीं है।

हमारी राय में अपीलकर्ताओं को सही तरीके से दोषी ठहराया गया था और

इसलिए हम इस अपील को खारिज करते हैं। अपीलकर्ता जगन्नाथ प्रसाद को अपने जमानत बांड के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।